



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092020-222073
CG-DL-E-28092020-222073

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/ आश्विन 6, 1942

No. 266]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2020/ASVINA 6, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

मामला सं. एडी-ओ आई 26/2020

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सिलिकॉन सीलेंट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/31/2020-डीजीटीआर.—1. मै. अल्टोन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "सिलिकॉन सीलेंट जिसमें सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, और थर्मल पावर अनुप्रयोगों के निर्माण में प्रयुक्त सिलिकॉन सीलेंट शामिल नहीं हैं", (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद", या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सिलिकॉन सीलेंट जिसमें सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, और थर्मल पावर अनुप्रयोगों के निर्माण में प्रयुक्त सिलिकॉन सीलेंट” शामिल नहीं हैं
4. “सिलिकॉन सीलेंट” अधेसिव का तरल रूप है। विशिष्ट रूप से यह जेल की भांति दिखाई, महसूस होता है और कार्य करता है। यह अन्य आर्गेनिक पॉलीमर आधारित अधेसिव्स से भिन्न रासायनिक संघटक है। अन्य अधेसिव्स के विपरीत, सिलिकॉन उच्च और निम्न, दोनों प्रकार के तापमान में अपना लचीलापन और स्थिरता बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त, सिलिकॉन सीलेंट अन्य रसायनों, नमी और मौसम के प्रभाव के प्रति प्रतिरोधी है। इसके असफल होने की संभावना कम होती है जब इसे भवनों और वस्तुओं की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य अधेसिव्स के विपरीत, सिलिकॉन को संसाधित करने से तात्पर्य मूल रूप से इसे सूखने देना है। सिलिकॉन सीलेंट का प्रयोग आम तौर पर खिड़कियों के फ्रेम को सील करने के लिए किया जाता है क्योंकि वे जल-प्रतिरोधी सील उपलब्ध कराते हैं जो खराब मौसम की स्थितियों के विरुद्ध मजबूती बनाए रखते हैं। सिलिकॉन सीलेंट का प्रयोग दरारों को बंद करने के लिए किया जा सकता है। कई बार कई व्यक्ति इससे अपने घर आदि में सतह को समतल करने की कोशिश करते हैं जल-प्रतिरोधी सिलिकॉन सीलेंट सिंक और ऐसे अन्य क्षेत्रों के आस पास की जगह की मरम्मत के लिए आदर्शपूर्ण है जहां पानी अक्सर पाया जाता है। हालांकि, सिलिकॉन भार सहने वाली सीलों के लिए प्रयोग हेतु एक अच्छा पदार्थ नहीं है, फिर भी बहुत से निर्माण कार्यों में इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की जरूरत होती है। सिलिकॉन सीलेंट आम तौर पर सतहों जैसे प्लास्टिक, धातु और शीशा को एक साथ बंद करने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए एक्वेरियम को प्रायः सिलिकॉन से सील किया जाता है। खिड़कियों को प्रायः फ्रेमों में सिलिकॉन सीलेंट से सील किया जाता है क्योंकि यह मौसम प्रतिरोधी है। निर्माण कार्य/भवनों और शीशे संबंधी अनुप्रयोगों के अतिरिक्त, सिलिकॉन का प्रयोग आटोमोबाइल्स, एप्लाइसिस, सीलिंग केबल्स और इलैक्ट्रॉनिक्स डिवाइसिस में केबल्स और सेंसर्स को सील करने, घर, टाइलों, फ्लोरिंग आदि की बुनियादी मरम्मत में किया जाता है।
5. हालांकि, सिलिकॉन सीलेंट का प्रयोग बहुत से खंडों और अनुप्रयोगों में किया जाता है, पी यू सी के क्षेत्र में सोलर फोटोवोल्टैक मॉड्यूल्स और थर्मल पावर अनुप्रयोग के विनिर्माण में प्रयुक्त सिलिकॉन सीलेंट शामिल नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा अभी तक सिलिकॉन सीलेंट ऐसे प्रकार उत्पादित और आपूर्ति नहीं किए गए हैं। आवेदक द्वारा ऐसे प्रकारों को उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के समान न होने का दावा किया गया है और इसलिए ये पीयूसी के क्षेत्र से बाहर हैं।
6. पीयूसी का सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के तहत कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं किया गया है। पीयूसी का आयात अध्याय 32 और 35 के संबंधित उपशीर्षों के अंतर्गत किया जाता है और अन्य अध्यायों के तहत पीयूसी के आयात को वर्जित नहीं किया गया है।

समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं और संबद्ध देश से आयात की जा रही वस्तुएं अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में तुलनीय है। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक ने आगे दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और स्थिति

8. यह आवेदन मै. अलस्टोन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और संबद्ध वस्तुओं के एक अन्य उत्पादक अर्थात् मै. एच.पी. अधेसिव प्रा. लिमिटेड द्वारा समर्थन दिया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि न तो उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या

किसी उत्पदक अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि आवेदक भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और उचित जांच के पश्चात प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

कथित पाटन का आधार

(क) चीन के लिए सामान्य मूल्य

9. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ-7 की शर्तों में निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) का उदाहरण दिया है और कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) की शर्तों में संबद्ध वस्तुओं को उत्पादित करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियां अभिभावी हैं। आवेदक ने दावा किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसरण में निर्धारित किया जाना चाहिए। तीसरे देश की उचित बाजार अर्थव्यवस्था में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों या निर्मित मूल्य या भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश की कीमतें न तो आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं न ही यह सूचना प्राधिकारी को किसी सरकारी स्रोत से उपलब्ध हुई है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य को लाभ को शामिल करने के लिए, भली भांति समायोजित, भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत के आधार पर निर्धारित तिकिया गया है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ के परिवर्धन के पश्चात भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है।

(ख) निर्यात कीमत

10. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय माल भाड़ा व्ययों और वैट के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

(ग) पाटन मार्जिन

11. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से पीयूसी के संबंध में पाटन मार्जिन के न्यूनतम सीमा से अधिक होने तथा महत्वपूर्ण मात्रा में होने का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

12. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने घरेलू उद्योग को समग्र रूप से और उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कीमत ह्रास के रूप में जांच की अवधि के दौरान कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उनका निष्पादन घरेलू उद्योग पर बिक्री कीमत से कम कीमत पर बिक्री, बिक्रियों की लागत और क्षति रहित कीमत पर संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन, क्षमता उपयोग में गतिहीनता, और घरेलू बिक्रियों की मात्रा और बाजार हिस्से विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है। लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट के परिणामस्वरूप विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि हाल ही में आयातों में हुई ऐसी महत्वपूर्ण वृद्धि और घरेलू बिक्री कीमतों पर आयात कीमतों के ह्रासकारी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग पर क्षति का और अधिक खतरा है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। यह कहा गया है कि संबद्ध देश की तुलना में काफी उच्च कीमत पर अन्य देशों से आयात किए गए हैं और उन्हें कथित क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

13. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं।

संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

जांच की अवधि (पीओआई)

15. जांच अवधि (पीओआई) के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2019 (12 माह) है तथा क्षति अवधि में अप्रैल 2016 –मार्च, 2017, अप्रैल 2017- मार्च, 2018, अप्रैल 2018 –मार्च 2019 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

16. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

17. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd12-dgtr@gov.in, ad11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एम एस वर्ड फॉर्मेट और डाटा फाइलें एम एस एक्सेल फॉर्मेट में होनी चाहिए।
18. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर पैरा 17 में उल्लिखित ई-मेल पते पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

21. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित ई-मेल पत्तों adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd12-dgtr@gov.in, ad11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
24. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
25. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
26. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशिकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
28. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
30. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

31. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

32. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बि. बि. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2020

Case No. AD-OI-26/2020

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Silicone Sealants ” originating in or exported China PR.

F. No. 06/31/2020-DGTR.—1. M/s Alstone Industries Pvt. Ltd (hereinafter also referred to as “Applicant”) has filed an application seeking initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Silicone Sealants excluding silicon sealants used in manufacturing of solar photovoltaic modules, and thermal power applications” (hereinafter also referred to as “Subject goods” or “Product Under Consideration” or “PUC”) from China PR (also referred to as “Subject country”) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”).

2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports of subject goods from China PR and has requested for imposition of anti- dumping duty on such the imports of the subject goods from the subject country.

Product under Consideration (PUC)

3. The product under consideration is “Silicone Sealants excluding silicon sealants used in manufacturing of solar photovoltaic modules, and thermal power applications” originating in or exported China PR.
4. Silicone sealant is a liquid form of adhesive. Typically, it looks, feels, and acts like a gel. It has a different chemical make-up from other organic polymer-based adhesives. Unlike other adhesives, silicone keeps its elasticity and stability in both high and low temperatures. Furthermore, silicone sealant is resistant to other chemicals, moisture, and weathering. This makes it less likely to fail when used in construction of buildings and repairing objects. Unlike some adhesives, silicone sealants must cure. Curing silicone basically means letting it dry. Silicone Sealants are commonly used to seal windows to frames, as they provide a water-resistant seal that maintains a strong hold against harsh weather conditions. Silicone sealants can be used for caulking cracks. Sometimes individuals may use it to try and level surfaces in their home etc. Water-resistant silicone sealants are ideal for repairing areas around sinks and other areas where water is frequently found. Even though silicone isn’t a good substance to use for weight-bearing seals, there is still a need for its powerful adhesive properties in many construction jobs. Silicone sealants are commonly used to bind surfaces such as plastic, metal, and glass together. For example, aquariums are often sealed with silicone. Windows are often sealed to frames with silicone sealants since it is weather resistant. Apart from construction/building and glass related applications, Silicone Sealants are used in automobiles, appliances, sealing cables and sensors in electronic devices, basic repairs around the house/tiles/floorings etc.
5. Though Silicone Sealants are used in multiple segments and applications, Silicone Sealants used in the manufacturing of Solar Photovoltaic Modules and Thermal Power applications are not covered in the scope of PUC as the said types were not produced and supplied by the petitioner so far. Such types are claimed to be not identical to the subject goods produced by the applicant and are hence excluded from the scope of PUC.
6. The PUC does not have any dedicated classification under Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975). The imports of PUC have been taking place under respective subheadings of Chapter 32 and 35 and the import of PUC under some other chapters as well is not ruled out.

Like Article

7. The Applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject country is comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

8. The Application has been filed by M/s Alstone Industries Pvt. Ltd and is supported by another producer of the subject goods in India namely M/s HP Adhesives Pvt. Ltd. The Applicant has claimed that they have neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. Considering the information on record, the Applicant accounts for a major proportion of the Indian production. In view of the above and after examination, the Authority notes that the Applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Basis of Alleged Dumping**a) Normal Value for China PR**

9. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The Applicant has claimed that for China, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The prices or constructed value of the product under consideration in the appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant nor is this information available with the Authority from any public source. Thus, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

b) Export price

10. The Authority has computed the export price for subject goods for the subject country based on transaction-wise import data from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, inland freight expenses and VAT.

c) Dumping margin

11. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of the import of PUC from the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the PUC from subject country is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

Evidence of injury and causal link

12. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having been caused from the alleged dumped imports during the Period of Investigation in the form of increase volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting and price suppression effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that their performance has been adversely impacted resulting in stagnancy in production, capacity utilization and domestic sales volumes and declines in market share. The profitability, cash profits

and return on capital employed has decreased as a result of increase in imports of product under consideration from subject country at a price below the selling price, cost of sales and non-injurious price of the domestic industry. The Applicant has also claimed that there is a further threat of injury to the domestic industry in view of such significant increase in imports in the recent time and suppressing effect of import prices on domestic selling prices. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject country. It has been stated that the imports from other countries have been at a much higher price than subject country and cannot be treated as cause of alleged injury.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

13. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Country

14. The subject country for this investigation is China PR.

Period of Investigation (POI)

15. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2019 to 31st March 2020 (12 Months). The injury investigation period will cover the periods April 2016- March 2017, April 2017-March 2018, April 2018- March 2019 and the POI.

Procedure

16. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

17. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd12-dgtr@gov.in, ad11-dgtr@gov.in . It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
18. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 17 above.
20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

21. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in , adv13-dgtr@gov.in, dd12-dgtr@gov.in, ad11-dgtr@gov.in, within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti- dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

23. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
24. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non Confidential versions separately.
25. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
26. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
30. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

31. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

32. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority